पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 22, अंक 4/2021

प्रदेश में गुड समेरिटन के लिए जन जागरूकता जरूरी

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यदि तुरंत चिकित्सा मिल जाए तो उसका जीवन बचाया जा सकता है। जो भी व्यक्ति 'अच्छे मददगार' (गुड समेरिटन) के रूप में घायल व्यक्ति की मदद करता है, उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाए।

'कट्स' द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से जयपुर में 'गुड समेरिटन गाइडलाइन्सः चैलेंज एण्ड वे फारवर्ड' पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बीजू जोसफ जॉर्ज, एडिशनल डाइरेक्टर जनरल, पुलिस सतर्कता, राजस्थान ने विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए यह बताया। उन्होंने बताया कि राज्य में 2020 के दौरान 19,114 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें करीब 9200 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इनमें से 50 प्रतिशत लोगों को बचाया जा सकता था, यदि उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया होता।

कार्यक्रम में विशेष अतिथि महेन्द्र सोनी, आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि पुलिस विभाग सभी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसके लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित की जाती है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाना हम सभी का दायित्व होना चाहिए।

कार्यशाला के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने गुड समेरिटन को परिभाषित करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'कट्स' द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राज्य के अजमेर, कोटा, जयपुर और उदयपुर में गुड समेरिटन के प्रति आम लोगों को जागरूक बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई है। अभी भी प्रदेश में 80 फीसदी लोगों में गुड़ समेरिटन गाइडलाइन की पूरी जानकारी का अभाव है। डॉ. नरोत्तम शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम ने सुझाव दिया कि सरकार को शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूली पाठ्यक्रम में गुड़ समेरिटन को भी विषय रूप में शामिल करना चाहिए।

तकनीकी सत्र के पहले 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से 'कट्स' द्वारा संचालित 'गुड़ समेरिटन' के अधिकार व दायित्वों, जागरूकता कार्यक्रमों और गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। 'कट्स' के मधुसूदन शर्मा ने तकनीकी सत्र का संचालन किया।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार 'कट्स' द्वारा जयपुर में आयोजित उक्त राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान महेन्द्र सोनी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, राजस्थान सरकार द्वारा बूंदी जिले के पत्रकार पीयूष शर्मा को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

पीयूष शर्मा बूंदी जिले के केशोराय पाटन गांव के मूल निवासी हैं तथा हलधर टाइम्स से जुड़े हुए हैं। उन्होंने वर्ष 2020 के दौरान 'कोरोना महामारी के दौरान बढ़ती बेरोजगारी' पर कई रोचक एवं तार्किक स्टोरियां प्रकाशित कर आमजन में जागरूकता लाने एवं जनचेतना जागृत करने का काम किया है।

इस अंक में...

वैक्सीन की बर्बादीः कब रुकेगी ये लापरवाही .. 3
स्कूलों में वसूल रहे मनमाना विकास शुल्क ... 4
खूब दौड़ी सरकार की 'घोषणा एक्सप्रेस' 7
बिजली बिल नहीं चुका रहे सरकारी महकमे .. 8
ग्रामीण घरों में पहुंचेगा शुद्ध पेयजल 9

जनता की शक्ति से ही मिलता है सरकार को अधिकार! इसे कायम रखने के लिए आप हैं जिम्मेदार!!

महापौर सम्मेलन- शक्तियों के अभाव में शहरी निकायों की कार्य प्रणाली कमजोर

कट्स इंटरनेशनल द्वारा भारत सरकार के नीति आयोग और दि एशिया फाउन्डेशन के संयुक्त तत्वाधान में महापौर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन राजस्थान सिटी मेयर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म परियोजना के तहत किया गया। सम्मेलन में राजस्थान के विभिन्न जिलों से महापौर, उप महापौर तथा स्थानीय निकायों के सभाध्यक्ष सम्मिलित हुए। चर्चा में यह बात निकलकर आई कि शक्तियों के अभाव में शहरी निकायों की कार्य प्रणाली कमजोर रही है, जिस कारण कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं।

सम्मलेन में भरतपुर के महापौर अभिजीत कुमार ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, इससे शहरों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। समस्याओं से निपटने हेतु जन प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए।

सम्मेलन में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि महापौर सम्मेलन के माध्यम से स्थानीय निकायों के महापौर एवं उप महापौर को अपनी कार्य प्रणाली पर विचार-विमर्श के लिए अवसर प्रदान करता है। सम्मेलन में स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त निदेशक संजीव कुमार पाण्डेय ने कहा कि शहरी निकायों में सभी जन प्रतिनिधियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। साथ ही जन प्रतिनिधियों द्वारा जो भी अच्छे एवं बुरे कार्य किए जा रहे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। सम्मलेन में 'राजस्थान शहरी निकायः अवसर एवं चुनौती' नामक 'कट्स' के अध्ययन का प्रस्तुतिकरण अमर दीप सिंह, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दिया गया।

जयपुर ग्रेटर के उप महापौर पुनीत कर्णावट ने कहा कि राजस्थान के शहरी निकाय स्वच्छता रैंकिंग में बहुत पीछे है। शहरी निकायों में हमेशा बजट का अभाव रहता है। डॉ. देबोलिना कुण्डु, प्रोफसर, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अरबन अफेयर्स ने अपने प्रस्तुतिकरण में राजस्थान के शहरी निकायों की स्थिति के बारे में बताया। प्रजा फाउन्डेशन के मिलिन्द महास्के ने अपने प्रस्तुतिकरण में शहरी निकायों की कार्य प्रणाली के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों का शहरों के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने शहरी सूचकांक 2021 का हवाला देते हुए राजस्थान के शहरों की खराब स्थिति का वर्णन किया।

राजस्थान एस.डी.जी. 12 लक्ष्यों के कार्यान्वयन में पिछड़ रहा है - विशेषज्ञ

एस.डी.जी. 12 जो कि 'सतत् उपभोग और उत्पादन' के रूप में जाना जाता है, के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जागरूकता, समन्वय और डेटा की कमी एक प्रमुख चिंता का विषय है। विभागों में बजट और तकनीकी कर्मचारियों की कमी के साथ-साथ अपर्याप्त निगरानी और रिपोर्टिंग एस.डी.जी. क्रियान्वयन में राज्य स्तर की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रतीत होती है।'

उक्त विचार जॉर्ज चेरियन, निदेशक, 'कट्स' इंटरनेशनल जयपुर ने एस.डी.जी.परामर्श के उद्घाटन के दौरान व्यक्त किए, जिसका आयोजन नीति आयोग और स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन (एस.एस.एन.सी.) की साझेदारी में 'कट्स' द्वारा किया गया था। यह 'कट्स' द्वारा 'एस.डी.जी.12ः एक उपभोक्ता परिप्रेक्ष' शीर्षक के तहत किए गए अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में से एक था।

उद्घाटन सत्र के दोरान सुंदर नारायण मिश्रा, वरिष्ठ सलाहकार, एस.डी.जी., नीति आयोग, भारत सरकार ने 'कट्स' के अध्ययन के निष्कर्षो का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान एस.डी.जी. 12 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ रहा है। हालांकि राज्य स्तर पर कई नवाचार किए गए हैं। उन्होंने साझा किया कि एस.डी.जी. 12 के लिए निगरानी और डेटा संग्रह की आवश्यकता है। इस चिंता को दूर करने में नीति आयोग के तहत प्रयास किए जा रहे हैं।

आंनद मोहन, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदेश में कैसे काम किया जा रहा है। उन्होंने ई-कचरे को कम करने के संभावित समाधान और समाज में स्थायी उपभोग व्यवहार की जरूरत जताई। कार्यक्रम में पुनीता सिंह, संयुक्त निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार एवं हितबल्लभ शर्मा, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ने भी विभिन्न जानकारियां साझा की। 'कट्स' के अमर दीप सिंह ने सत्र का संचालन किया। कार्यक्रम में करीब 50 से अधिक संगठनों की भागीदारी रही।

वैक्सीन की बर्बादीः कब रुकेगी ये लापरवाही

एक तरफ तो सरकारें सबसे अधिक कोविड़ टीका लगाने की उपलब्धियां गिना रही हैं, वहीं टीके की बर्बादी को रोकने में नाकाम हो रही हैं। टीका बर्बादी के मामले में पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश पहले नंबर पर है। वहीं राजस्थान का स्थान तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 9.77 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। उत्तर प्रदेश में 18.49 करोड़ व राजस्थान में 7.66 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है।

मध्य प्रदेश में अब तक 16,47,955 टीके बर्बाद हुए हैं, राजस्थान के लिए यह आंकड़ा 6,86,224 है। टीके की कुल बर्बादी में 37.28 फीसदी हिस्सा इन्हीं दोनों राज्यों का है। अगर पूरे देश की बात करें तो 62,58,722 डोज बर्बाद हो चुकी हैं। निजी संस्थानों को शामिल करें तो यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। टीके की बर्बादी के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि एक्सपायरी डेट, टीका गर्मी के संपर्क में रहने या फिर टीका टूट गया हो आदि । *(दै.भा., 19.12.21)*

प्रदेश में नहीं बन पा रहे किसान ऊर्जादाता

प्रदेश में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही। प्रदेश के 623 किसानों ने अपनी बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने में खूब रुचि दिखाई है। लेकिन बैंक उन्हें लाखों रुपए का ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। योजना के दूसरे साल में महज आठ प्लांट लग पाए हैं।

स्थिति यह है कि कंपनियां किसानों से भूमि खरीदकर या बीस पच्चीस साल के लिए लीज पर लेकर सोलर प्लांट लगाकर बिजली सरकार को बेचती है। इससे किसान की भूमि कंपनियों की गिरफ्त में आने की आशंका बन रही है। योजना के मुताबिक किसान खुद ऊर्जादाता बनकर अतिरिक्त आय सृजन नहीं कर पा रह हैं। *(रा.प., 06.10.21)*

लेटलतीफीः मकान मिलना हुआ मुश्किल

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रदेश के गांवों में इस साल के लिए चुने गए तीन लाख से भी अधिक परिवारों को लेटलतीफी के चलते मकान मिलना मुश्किल होगा। केंद्र सरकार से मिले 3.97 लाख आवासों की मंजूरी होने के बावजूद आवासों की स्वीकृति से पहले हर ग्राम पंचायत में लाभार्थियों की श्रेणीवार वरीयता निर्धारित होनी है।

प्रदेश की 11 हजार से अधिक पंचायतों में से तकरीबन 8 हजार पंचायतों में यह वरीयता सूची पूरी तरह तैयार ही नहीं हो पाई है। सरकार ने जल्द वरीयता तय करने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन प्रक्रिया देखते हुए यह कार्य इतना आसान नहीं दिख रहा है। *(रा.प., 20.10.21)*

पड़े-पड़े ई-मित्र प्लस मशीनें हुई कबाड़

राज्य सरकार ने ई-मित्र से जुड़ी सेवाओं को जनता के लिए सस्ता व सुलभ बनाने के लिए पंचायतों, उपखंड कार्यालयों, जिला कलेक्टर कार्यालयों में ई-मित्र मशीनें लगाई। लेकिन, डिजिटल लिटरेसी और कनेक्टिविटी के अभाव में ये मशीनें काम नहीं आ पा रही हैं।

पूरे प्रदेश में 9891 ई-मित्र मशीनें हैं, जिनमें से करीब 1100 मशीनें कबाड़ में पड़ी हैं। सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग ने मशीनें तो लगा दी मगर लोगों को इसका इस्तेमाल करना नहीं सिखाया पाए। वर्षों से ये मशीनें कार्यालयों में लगी हुई हैं और कबाड़ हो रही है। प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति यह है कि ई-मित्र संचालक मशीन की आई-डी बंद ना हो इसके लिए महीने में एक बार जाकर स्वयं इन मशीनों से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। *(रा.प., 18.12.21)*

फूड सप्लीमेंट के जरिए बिके 'जहर'

प्रदेश में दवाओं की दुकानों सहित डिपार्टमेंटल स्टोर पर बेचे जा रहे फूड सप्लीमेंट की जांच पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग छह साल से मौन साधे हुए है। रोजाना करोड़ों रुपए की बिक्री वाले इन उत्पादों की जांच का प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत है और इसके लिए विभाग के पास पूरा अमला मौजूद है। लेकिन इन उत्पादों की जांच के नाम पर खानापूर्ति ही की जा रही है।

विभाग ने 2015-16 में फूड सप्लीमेंट की जांच के लिए अभियान चलाया था। उस समय कुछ नमूने लिए गए थे, लेकिन जांच में क्या हुआ? अमानक या उपयोग करने लायक नहीं पाए जाने वाले विक्रेताओं पर क्या कार्रवाई की गई? विभागीय अधिकारी यह बता पाने की स्थिति में नहीं हैं। *(रा.प., 24.11.21)*

पौधारोपण में इच्छाशक्ति का पतझड़

राजस्थान में राज्य सरकार ने सघन पौधारोपण अभियान शुरू किया। इसके तहत हर शहर में गांधी वाटिका स्थापित करने और वहां कम से कम डेढ़ सौ पौधे लगाने की बाध्यता की गई। पिछले वर्ष कोरोनाकाल में ही केंद्र सरकार ने नगर वन बनाने के लिए कहा था, लेकिन नगरीय निकायों ने रुचि नहीं ली। हर शहर में 10 से 50 हैक्टेयर क्षेत्रफल में नगर वन विकसित किया जाना था।

केंन्द्र सरकार इसके लिए दो करोड़ रुपए प्रति नगर फंडिंग देगी। इसके पीछे प्रदेश में हरियाली को 7 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी तक लाना है। लेकिन इस दिशा में सरकारी स्तर पर इच्छाशक्ति के अभाव के चलते कारगर प्रयास अमल में नहीं लाए जा रहे और करोड़ों रुपए खर्च करने और 37 करोड़ से भी ज्यादा पौधे लगाने के बावजूद हरियाली का दायरा नहीं बढ़ पाया है। *(रा.प., 15.10.21)*

धरातल पर नहीं उतरे रोजगार देने के वादे

प्रदेश में कोरोना की पहली व दूसरी लहर के दौरान सरकार की ओर से प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के वादे तो खूब किए, लेकिन जमीनी स्तर पर इनकी स्थिति कागजी साबित हुई। सरकार ने कामगारों को कौशल विकास निगम व स्वयं सहायता समूहों के जरिए प्रशिक्षण दिलाने का दावा किया, लेकिन प्रदेश के 12 लाख से अधिक कामगार योजना शुरू होने का इंतजार करते रहे।

कौशल विकास निगम के अधिकारी व कर्मचारी फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार में अपना कौशल दिखाने में लगे रहे। जिससे अभी तक प्रशिक्षण केंद्र ही शुरू नहीं हुए। सरकार ने

कामगारों के लिए ऋण दिलाने का वादा भी किया लेकिन उसमें भी कामगारों को राहत नहीं मिली। राहत नहीं मिलने पर कोई रोजी-रोटी के जुगाड़ में फिर से परदेश चला गया तो किसी ने खुद रोजगार की नई राहें तलाश ली।

(रा.प., 31.10.21)

पंजीयन विभाग में करोड़ों का घोटाला

प्रदेश में रजिस्ट्री करने की आड़ में करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। अब तक 5 जिलों में करीब 700 रजिस्ट्री में घोटाला होने की बात सामने आई है। यह घोटाला रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेज का पंजीयन कराने के दौरान स्टाम्प शुल्क की ई-ग्रास के जरिए राशि जमा कराने की फर्जी रसीदें लगाकर किया गया।

बड़ी बात यह है कि यह घोटाला दो साल से चल था लेकिन मिलीभगत के चलते पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधिकारी भी आंखे मूंदे बैठे रहे। घोटाले की मुख्य वजह डीडराइटर व अन्य उन लोगों पर विश्वास करना है जो लोगों की रजिस्ट्रियां कराते हैं। प्रथम दृष्टया जांच में यह सामने आया कि ज्यादातर मामलों में रजिस्ट्रेशन व स्टाम्प शुल्क की दस फीसदी रकम ही जमा हुई है, जबकि 90 फीसदी रकम का कोई अता-पता नहीं है। डीडराइटर व अन्य बिचौलिए अब गायब हो गए हैं।

(रा.प., 13.10.21, 15.10.21)

जनधनः बीमा किश्त की रसीद नहीं?

ग्रामीण क्षेत्रों में जनधन खाते से बैंक द्वारा 12 रुपए बीमा प्रीमियम की किश्त काटी जाती है, लेकिन खाताधारकों को उसकी रसीद नहीं मिलती। जानकारी व शिक्षा के अभाव के चलते खाताधारकों को दुर्घटना होने पर मुआवजा नहीं मिल पाता। बैंक जो खाताधारकों से करोड़ों रुपए काटती है, वह सीधा बीमा कंपनियों की जेब में चला जाता है।

यह तथ्य ग्रामीण विकास योजनाओं की क्रियान्विति देखने पांच दिवसीय दौरे पर आई संसद की स्थाई समिति के सामने आया। समिति के अध्यक्ष सांसद प्रतापराव जाधव ने इस पर चिंता जाहिर की और समस्या के हल के लिए ग्रामीण विकास सचिव को सलाह दी गई कि इस बारे में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कृषि सहायक आदि बैंकों से तालमेल रखे और ऐसे मामलों में पीड़ित को दावा पेश करने में सहायता करें।

(रा.प., 17.11.21)

बैंक ने गरीबों से वसूले 164 करोड़ रुपए

देश में आम आदमी को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के नेक इरादे से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 2017 से 2019 तक महीने में चार से अधिक डिजिटल लेन-देन पर हर बार 17.70 रुपए शुल्क वसूलता रहा। इस दौरान बैंक ने 12 करोड़ जनधन खातधारकों से 164 करोड़ रुपए कमाए। आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि बैंक ने शुल्क वसूलते समय जनधन खातों से जुड़ी शर्त का उल्लंघन किया।

वित्त मंत्रालय में शिकायत पर 1 जनवरी 2020 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने खाताधारकों से लिए गए शुल्क को वापस करने का आदेश जारी किया तब एसबीआई ने 17 फरवरी 2021 से राशि लौटाना शुरू किया। लेकिन अब भी 164 करोड़ रुपए खाताधारकों को लौटाए जाने बाकी है। खाता धारकों को काटी गई राशि पर अब तक का ब्याज का भी हक बनता है।

(दै.भा., 22.11.21)

'कुसुम' योजना में चल रहा गड़बड़झाला

सौर ऊर्जा के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की 'कुसुम' योजना में गड़बड़झाला चल रहा है। इसके लिए अजमेर डिस्कॉम ने न केवल मनमानी निविदा शर्तें रखी, बल्कि अपनों को उपकृत करने से भी नहीं चूके। मामला किसानों की जमीन पर सोलर प्लांट (सोलर पम्प सेट सहित) लगा सस्ती बिजली देने से जुड़ा है।

आरोप हैं कि अजमेर डिस्कॉम ने निविदा जारी की, जिसमें 4692 सोलर प्लांट के लिए करीब 96.06 करोड़ लागत सामने आई। लेकिन कंपनी द्वारा हाथ पीछे खींचने की आड़ लेते हुए उसी काम के लिए 117.14 करोड़ रुपए लुटा दिए गए। इससे डिस्कॉम को 21 करोड़ रुपए की चपत लगी। इसमें 50 प्रतिशत अतिरिक्त काम की स्थिति में यह आंकड़ा 32 करोड़ रुपए पहुंचता है। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी है, लेकिन जांच हो तो वास्तविक आंकड़ा सामने आए।

(रा.प., 23.11.21)

सीमा विकास के बहीखाते में मिली गड़बड़

भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती चार जिलों में बॉर्डर एरिया डवलपमेंट योजना के तहत बीते आठ वर्षों में हुए विकास कार्यों पर खर्च के बहीखाते में अनियमितता उजागर हुई है।

योजना के तहत आठ विभिन्न विभागों के कार्यों के करीब 55 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र(यूसी)अब तक जारी नहीं हुए हैं, जबकि इस राशि के खर्च के कुल चार सौ से भी अधिक कार्य कराए गए थे। यह यूसी संबंधित विभाग का काम पूरा होने और उसमें तय राशि खर्च होने का प्रमाण होता है। इतनी बड़ी राशि का लेखा-जोखा नहीं होने की यह गड़बड़ी हाल ही बीएडीपी को लेकर की गई कलेक्टरों से बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य के सामने आई है।

(रा.प., 02.12.21)

स्कूलों में वसूल रहे मनमाना विकास शुल्क

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन तो बढ़ गया लेकिन इसके मुकाबले सुविधाएं कम हो गई है। ऐसे में स्कूली बच्चों से विकास शुल्क के नाम पर मनमानी वसूली शुरू हो गई है। हैरानी की बात यह है कि विकास शुल्क वसूलने का कोई तयशुदा नियम नहीं है। कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों से 500 से 2100 रुपए तक विकास शुल्क वसूला जा रहा है।

इस मनमानी वसूली से छात्रों के अभिभावकों की भी मुश्किल बढ़ गई है और उन्होंने इसका विरोध भी जताया है। खास बात यह है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक स्कूल को नामांकन के हिसाब से फैसिलिटी ग्रांट के रूप में एक लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। इसके बाद भी विद्यालय प्रबंध समितियां मनमाना शुल्क निर्धारित कर बच्चों पर आर्थिक बोझ डाल रही है।

(रा.प., 23.12.21)

भ्रष्टाचार पर चला एसीबी का डंडा

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बीते एक साल में रेकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। एसीबी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर 2020 के बाद एक साल में भ्रष्टाचार के 525 मामले दर्ज हुए है। इस अवधि में दर्ज मामलों को लेकर एसीबी ने तुरंत कार्रवाई भी की है। लगभग 80 प्रतिशत मामलों में चालान पेश किया जा चुका है। अन्य मामलों में भी अनुसंधान तेजी से किया जा रहा है। इस अवधि में आइएएस, आइपीएस, आरएएस, आरपीएस ही नहीं बल्कि सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारी-कर्मियों को भी पकड़ा गया है।

यह जानकारी देते हुए एसीबी डीजी बीएल सोनी ने बताया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अब लोग जागरूक हुए हैं, एसीबी की हेल्पलाइन नंबरों पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई। यही कारण रहा कि सूचना मिलने के साथ ही एसीबी सतर्क हो गई और भ्रष्टाचार की परतें खोल दी। *(रा.प., 10.10.21)*

घूसखोरी में राजस्थान अव्वल नंबर पर

भ्रष्ट देशों की सूची में भारत की स्थिति और भी ज्यादा खराब हुई है। यहां हर दूसरे व्यक्ति ने रिश्वत देने की बात मानी है। भारत में 74 फीसदी लोगों का कहना है कि पिछले 3 साल में रिश्वतखोरी बढ़ी है। यहां अधिकारी कर्मचारी और नेता भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के शिकंजे में फंस रहे हैं।

वर्ष 2020 में देश भ्रष्टाचार के मामले में 77वें स्थान पर था। ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 की हालिया रिपोर्ट में अब भारत 82वें स्थान पर है। इंडिया करप्शन सर्वे के अनुसार घूसखोरी में राजस्थान सबसे आगे है। यहां 78 फीसदी लोगों ने काम के बदले रिश्वत देने की बात मानी है। लोगों ने माना है कि पुलिस, अदालत, सरकारी अस्पताल और बिजली पानी जैसी सेवाएं भी बिना घूस के नहीं मिलती। *(रा.प., 06.12.21)*

गांवों के संग अभियान में भ्रष्टाचार

प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। शाहपुरा के चिमनपुरा गांव में आयोजित शिविर में कृषि भूमि को आवासीय में कन्वर्जन करने के एवज में कनिष्ट सहायक जितेन्द्र कुमार ब्यास को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 20 हजार रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

एसीबी के परिवादी ने शाहपुरा तहसील में जितेन्द्र कुमार से संपर्क किया तो उसने काम के बदले 65 हजार रुपए मांगे। परिवादी ने उसे 25 हजार रुपए फीस और 20 हजार रुपए घूस के बतौर दे दिए। शेष 20 हजार रुपए काम होने पर देना तय हुआ। जितेन्द्र कुमार ने बाकी 20 हजार रुपए लेने के लिए परिवादी को आयोजित शिविर में बुलाया जहां मौजूद एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। *(रा.प., 12.11.21)*

मुखिया के सामने भ्रष्टाचार पर मुहर

बिड़ला सभागार, जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षकों से पूछा 'हम सुनते हैं कि तबादले के लिए पैसे खिलाने पड़ते हैं। बताइये यह सही बात है या नहीं। मुझे नहीं मालूम।' शिक्षक बोले - 'हां'। सीएम ने एक बार फिर पूछा -'पैसे देने पड़ते हैं क्या?' शिक्षकों ने ओर जोर से कहा -'हां'।

मुख्यमंत्री हैरान हो गए। बोले - 'कमाल है।' उनकी बात पर तालियां बजने लगी तो सीएम बोले-यह बहुत ही दुःखदायी है कि शिक्षक पैसे देकर तबादला कराने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए कोई तबादला पॉलिसी बने। कार्यक्रम में सीएम के भाषण के खत्म होते ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई देते हुए कहा- मेरे शिक्षामंत्री रहते हुए स्टाफ ने किसी से एक चाय भी पी हो तो बता देना। *(दै.भा. एवं रा.प., 17.11.21)*

एसीबी चलाएगा अनूठा अभियान

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनूठा अभियान चलाएगा। इसके तहत एसीबी प्रदेश के 51 गांवों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए गोद लेगी। अभियान के दौरान गांवों में लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक किया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने बताया कि अभियान में एसीबी के अधिकारी व कर्मचारी जन कल्याणकारी योजनाओं को त्वरित गुणात्मक स्तर पर क्रियान्वित करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ प्रयास करेंगे। *(रा.प. एवं दै.भा., 04.12.21)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	राशि (रुपए में)	स्त्रोत
जयपुर	राहुल बोडके	सहायक प्रबंधक, बीवीजी कंपनी	75,000	रा.प., 27.10.21
अजमेर	डॉ. मनोज स्वामी	मेडि. ज्यूरिस्ट, राज. यज्ञनारायण अस्पताल, किशनगढ़	1,00,000	दै.भा., 27.10.21
अजमेर	कंवरपाल रोहित शर्मा	थाना प्रभारी, रूपनगढ़ थाना प्रभारी, अजमेर दलाल	1,45,000	रा.प. एवं दै.भा., 30.10.21
अलवर	सुभाषचंद यादव	हेड कांस्टेबल, किशनगढ़ वास, अलवर	40, 000	दै.भा., 30.10.21
झालावाड़	विनोद कुमार खटीक	अधीक्षण अभियंता, कालीसिंध थर्मल	85,000	रा.प., 03.11.21
अलवर	बीना गुप्ता कुलदीप	सभापति, नगर परिषद अलवर बीना गुप्ता का बेटा	80,000	दै.भा. एवं रा.प.,23.11.21
जयपुर	पंकज व दिव्य प्रकाश	जेईएन, आयकर विभाग	1,50,000	रा.प. एवं दै.भा, 15.12.21

जलवायु शिखर सम्मेलन
मोदी ने दिया जागरूकता पर जोर

ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 'कोप-26' के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी को जागरूक बनाने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में जलवायु नीतियों को शामिल करने की जरूरत है। मोदी ने कहा, भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन 'शुद्ध शून्य' का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्रांति ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़कर पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हम सूर्य के माध्यम से प्रकृति से फिर से जुड़कर मानवता के भविष्य को बचा सकते हैं। मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के साथ संयुक्त रूप से 'एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड' की पहल शुरू करते हुए यह बात कही। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण घोषणा भी की कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जल्द ही एक ऐसा सौर कैलकुलेटर बनाने जा रही है, जो किसी भी जगह की सौर ऊर्जा संभावनाओं को नाप सकेगा। *(रा.प., 02.11.21, 03.11.21)*

प्रदेश के चार जिलों में आधे गरीब

नीति आयोग की ओर से पहली बार गरीबी का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक राज्यों में जहां बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीबी है, वहीं राजस्थान में भी गरीबी के आंकड़े चौंकाने वाले साबित हुए हैं। यहां कुल आबादी के मुकाबले 29.46 फीसदी प्रदेशवासियों को गरीबी में गुजर बसर करना पड़ रहा है।

जारी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो गरीबी में राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। यहां शहरी क्षेत्र में 11.52 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्र में 35.22 फीसदी आबादी गरीब हैं। प्रदेश के बाड़मेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले तो ऐसे है जहां आधी से भी ज्यादा आबादी गरीबी में अपना जीवनयापन कर रही है। प्रदेश में आज भी 42 फीसदी लोग कुपोषण से जूझ रहे हैं और 35 फीसदी आबादी के पास अपना घर तक नहीं है। *(दै.भा., 03.12.21)*

सतत् विकास लक्ष्यों की योजना

हम दुनिया का कायाकल्प करने की दहलीज पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक सम्पन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाएगा।

गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर, उपभोग व उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी।

बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी मजबूत

देश में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देने के लिए दूसरी बड़ी योजना है। यह प्रोजक्ट 64 हजार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है।

यह नेशनल हेल्थ मिशन से अलग होगा। इस मिशन से देश के 10 राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य व कल्याण केंद्रों (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) को मजबूती मिलेगी। इसके जरिए भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तैयार की जाएगी। मिशन के तीन लक्ष्य है- पहलाः बीमारी का पता लगाने और उसके इलाज के लिए विस्तृत सुविधाओं का निर्माण। दूसराः रोगी की जांच के लिए टेस्टिंग नेटवर्क और तीसराः जांच केंद्रों को बेहतर बनाया जाना है। *(रा.प., 26.10.21)*

तेजी से खत्म हो रहे प्राकृतिक संसाधन

दुनिया में बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने में तेजी से प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं। अमीर देश प्राकृतिक संसधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन कर रहे हैं। अमरीका, ब्रिटेन, कनाड़ा जैसे विकसित देश सबसे अधिक तो मालदीव, बांग्लादेश, श्री लंका जैसे गरीब देश अपेक्षाकृत बहुत कम दोहन कर रहे हैं।

यह खुलासा लीड्स यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में किए गए द सोशल शॉर्टफॉल एंड इकोलॉजिकल ओवरशूट ऑफ नेशंस शोध में हुआ है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित इस शोध को 30 साल में 148 देशों में 10 लाख से अधिक आबादी पर किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने वाले देशों की संख्या 30 साल में तेजी से बढ़ी है। *(रा.प., 24.11.21)*

कार्बन हटे तो पर्यावरण को सांस आए

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आगामी दशकों में बड़े स्तर पर कार्बन हटाने की आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का अनुमान है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए वर्ष 2050 तक हर वर्ष लगभग 10 गीगाटन (10 अरब टन) कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की आवश्यकता है।

क्योंकि, यदि मौजूदा गति से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता गया तो 2100 तक वैश्विक औसत तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ऐसे में 100 मिलियन डालर की इस प्रतियोगिता के जरिए जलवायु बचाने के लिए कार्बन हटाने का स्थाई हल देने वाले विश्व के उत्साही इनोवेटर्स को आमंत्रित किया गया है। *(रा.प., 11.11.21)*

भारत में बच्चों की मृत्युदर में आया सुधार

दुनियाभर में हर रोज 6575 से ज्यादा नवजातों की मौत हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कैसे 2030 तक दुनिया एसडीजी 3.2 के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही जारी लेवल्स एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी नामक रिपोर्ट को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। रिपोर्ट के हवाले से पता चलता है कि 2020 के दौरान दुनियाभर में करीब 50 लाख बच्चे अपना पांचवा जन्म दिवस भी नहीं देख पाए थे। जिनमें 24 लाख नवजात भी शामिल है।

भारत में पिछले तीन दशकों के दौरान काफी सुधार हुआ है, जहां 2020 में पांच वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों की मृत्युदर 32.4 प्रति हजार दर्ज की गई थी, जबकि 1990 में 126.2 प्रति हजारी रिकॉर्ड की गई थी। वहीं नवजातों की मृत्युदर 1990 में 57.4 थी, जो 2020 में घटकर 20.3 पर पहुंच गई थी।

निर्मल चरित्र हो पवित्र आत्मा! भ्रष्टाचार का तभी खात्मा!!

खूब दौड़ी सरकार की 'घोषणा एक्सप्रेस'

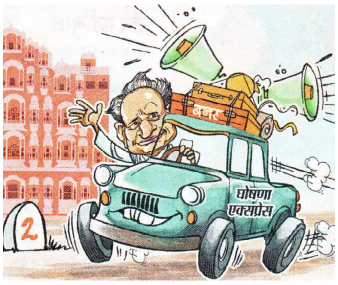

पिछले दो साल में कोरोना और वैश्विक मंदी ने जनजीवन से लेकर अर्थव्यवस्था तक सबकी रफ्तार को बेपटरी कर दिया है। लेकिन इस साल बजट भाषण से प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार की 'घोषणा एक्सप्रेस' खूब दौड़ी। पिछले दो बजट में करीब 625 घोषणाएं की गई। इनमें से करीब 425 इसी साल की है। इसे गहलोत सरकार के पिछले साल के संकट से उबरने का संकेत माना जा रहा है।

अब जनता से जुड़ी कई घोषणाओं पर काम किया गया है। इसके चलते कुछ घोषणाएं पूरी हो गई है तथा कुछ पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं कुछ घोषणाओं पर संशय बना हुआ है कि वह मार्च के अंत तक पूरी होंगी या नहीं? इसे लेकर जिलेवार पांच-पांच प्रमुख बजट घोषणाओं की स्थिति की पड़ताल की जा रही है। करीब 23 जिलों में काम भी शुरू हो चुका है। *(रा.प., 21.12.21)*

पीढ़ी दर पीढ़ी चले स्वच्छता अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को जीवन शैली और जीवन मंत्र बताते हुए कहा है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अभियान है। इसमें लोगों को ऐसे स्वच्छ व समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लेना है जो दुनिया के लिए सतत् जीवन की प्रेरणा बन सके। उन्होंने गांधी जयन्ती से एक दिन पहले स्वच्छ भारत मिशन शहरी और मिशन अमृत के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए यह संदेश दिया।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना देश के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के साथ ही अटल मिशन में नहीं आने वाले शहरों में दूषित व काले पानी का प्रबंधन किया जाएगा। यह मिशन रिड्यूस, रीयूज व रिसाइकल फॉर्मूले के आधार पर ठोस कचरे का निष्पादन करेगा। मिशन अमृत 2.0 में सभी घरों में नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जानी है। अगले पांच सालों में इन दोनों मिशन पर 4.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। *(रा.प. एवं दै.भा., 02.10.21)*

कोरोना सहायता योजना से मिली मदद

राज्य में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत चिन्हित में से 97 फीसदी कोरोना मृतकों के परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाई जा चुकी है। प्रदेश में 10064 पीड़ितों को 57 करोड़ 42 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इनमें 5699 विधवा महिलाएं, उनके 4220 बच्चे और 145 अनाथ बच्चे शामिल हैं, जिनके माता-पिता की कोरोना से मौत हो चुकी है।

पीड़ित परिवारों को घर बैठे यह सहायता राशि पहुंचाई गई है। अनाथ बच्चों को तत्काल एक लाख रुपए दिए गए हैं। उन्हें 18 वर्ष पूरे होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तब तक 2500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। राजकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। विधवाओं के बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक 1000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। साथ ही स्कूल ड्रेस, किताबों के लिए 2000 रुपए प्रत्येक बच्चे को दिए जाएंगे। *(दै.भा., 17.10.21)*

चिरंजीवी योजना से जुड़ेगा हर परिवार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में हर परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए मुख्यमंत्री ने 36 करोड़ रुपए के प्रावधान की मंजूरी दी है। अभियान का उद्देश्य सभी प्रदेशवासियों को यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज का लाभ देना है, ताकि उन्हें सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिल सके।

सरकार की ओर से चलाए जाने वाले इस अभियान में आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, पंचायतकर्मी फील्डस्तर पर सेवाएं दे रहे हैं। वह अपने क्षेत्र में सर्वे कर यदि रजिस्ट्रेशन से वंचित पांच परिवारों को योजना से जोड़ेंगे तो उन्हें 500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। *(रा.प., 11.12.21)*

सामाजिक योजनाओं में नहीं होगा घपला

प्रदेश में अब सामाजिक योजनाओं में घपले का खेल खत्म होगा। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आइटी का रोडमैप तैयार किया है। योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ा बदलाव सामने आएगा। सब कुछ अब ऑनलाइन होगा। विभिन्न योजनाओं के आवेदन और लाभ एक क्लिक पर मिल सकेंगे।

योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए जनाधार से आवेदन फार्मों को लिंक किया जाएगा। विधवा पेंशन, पालनहार योजना, छात्रों को छात्रवृत्ति, सामाजिक संस्थाओं को अनुदान, अजा जजा अत्याचार निवारण जैसे कई काम अब तुरंत हो सकेंगे। *(रा.प., 16.10.21)*

सुधर रही है खेतों की मिट्टी की सेहत

भारत सरकार ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। योजना के तहत किसानों की हर जोत के जीपीएस आधारित मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन कार्डों में भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों एवं विकारों को ध्यान में रख कर फसल के अनुसार किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा उर्वरक की सलाह दी जा रही है। अब तक देश के 22 करोड़ 56 लाख किसानों को कार्ड वितरित कर दिए गए हैं।

योजना के तहत देश में 429 मृदा परीक्षण, 102 चल मृदा परीक्षण और 8452 सूक्ष्म मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं मृदा परीक्षण का काम कर रही है। मृदाकार्ड बांटने के बाद के सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि उर्वरक की खपत 8 से10 फीसदी कम हुई है और फसलों की उपज में 5 से 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। *(रा.प., 04.12.21)*

नए भारत की नींव है 'गति शक्ति योजना'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 100 लाख करोड़ रुपए की लागत की बेहद महात्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति योजना शुरू की है। यह योजना देश की प्रगति की रफ्तार को नई शक्ति दे सकेगी। इससे अगले 25 साल के लिए नए भारत की नींव रखी जा रही है। इसके तहत बनने वाला मास्टर प्लान भारत के विश्वास को 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प तक ले जाएगा।

मोदी ने कहा, जिस तरह से सरकारी योजनाओं को बिना भ्रष्टाचार लोगों तक पहुंचाने में जन-धन खाते, आधार नंबर व मोबाइल (जैम) ने भूमिका निभाई है, वही काम ढांचागत सुविधाओं को खड़ा करने में गति शक्ति योजना करेगी। काम समय पर पूरा होगा जिससे भारत की साख को नई बुलंदी मिलेगी। *(रा.प., 14.10.21)*

बिजली बिल नहीं चुका रहे सरकारी महकमे

बिजली का उपभोग करने बाद भी ज्यादातर सरकारी एजेंसियां आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर बिल नहीं चुका रही जिसका बोझ आम उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई बिजली दर के रूप में उठाना पड़ रहा है। अभी प्रदेश में 2132.39 करोड़ रुपए बिजली शुल्क बकाया है। इससे बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है और लगातार लोन लिया जा रहा है। यही लोन राशि जनता से बिजली की बढ़ी हुई दर के रूप में ली जा रही है।

इस लोन राशि को टैरिफ में अंकित कर विद्युत विनियामक आयोग नई बिजली दर तय करने की गणना करता है। इससे आम उपभोक्ता पर आर्थिक भार बढ़ रहा है। स्वायत शासन, जलदाय व अन्य एजेंसियों का सीधे जनता से जुड़ाव है। जिससे डिस्कॉम नहीं चाहता कि कनेक्शन कटने की स्थिति में लोगों को कोई परेशानी हो। *(रा.प., 14.11.21)*

प्रदेश ला रहा बिजली संकट का समाधान

प्रदेश में 5 बिजली उत्पादन इकाइयां बंद होने से राजस्थान में बिजली संकट बढ़ गया। सरकार को 20 रुपए यूनिट तक बिजली खरीदनी पड़ी। लेकिन अगले 4-5 साल में राजस्थान को बिजली महज 2 रुपए यूनिट की दर से मिलेगी। यह रिनेबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) से संभव होगा। पावर स्टोरेज के लिए 2520 मेगावाट क्षमता का देश का पहला प्लांट ग्रीनको एनर्जी बारां के शाहपुर में लगेगा।

पाली के जैतारण में हाईब्रिड (विंड और सोलर) में 4500 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगेंगे। वही, सिरोही में जेएसडब्लू ने 1000 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। रीको के पास 4 कंपनियों की ओर से 36000 मेगावाट क्षमता के रिनेबल एनर्जी प्लांट लगाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरी ओर, 5 बड़ी कंपनियों ने 15000 मेगावाट क्षमता के रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। इससे राजस्थान में कुल 1.64 लाख करोड़ का निवेश आएगा और 7 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। *(दै.भा., 07.12.21)*

प्रदेश में नहीं रुक रही बिजली चोरी

राज्य में बिजली चोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। दो दिन में ही 3 करोड़ 15 लाख रुपए की बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। 1469 स्थानों पर जांच की इनमें 1387 जगह बिजली चोरी व 82 जगह पर दुरुपयोग होता मिला। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक नवीन अरोड़ा ने बताया कि विशेष सतर्कता जांच अभियान के तहत ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां बिजली छीजत ज्यादा हो रही थी।

इसी आधार पर यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई। जुर्माना राशि जमा करवाने के लिए लोगों को नोटिस जारी किए गए। निर्धारित समय में जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर विधिक कार्रवाई होगी। इसके अलावा डिस्कॉम की विजिलेंस टीम अब ऐसे बिजली कनेक्शन की भी जांच करेगी, जो लम्बे समय से बंद पड़े हैं। यह भी जांच की जा रही है कि कनेक्शन बंद होने के बाद भी वहां विद्युत उपयोग कैसे हो रहा है। *(रा.प., 21.11.21)*

सूरज से बिजली बनाकर बेच भी रहे हैं

जयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सूरज की रोशनी से बिजली बनाने का काम हो रही है। पिछले दो वर्षों में अब तक 25 स्थानों पर सोलर पैनल लगाने का काम पूरा हो चुका है। इसमें कॉलेज से लेकर अस्पताल और सरकारी महकमों की इमारतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं।

पिछले दो वर्ष की बात करें तो अब तक इन सौलर पैनल से 80 लाख यूनिट बिजली बनाई जा चुकी है। यह बिजली करीब 5 करोड़ 60 लाख रुपए की है। बिजली संकट से पहले ही ये सभी सौर ऊर्जा का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन गए हैं। आने वाले दिनों में करीब 10 सरकारी इमारतों पर भी पैनल लगकर तैयार हो जाएंगे। देखा जाए तो सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने से जहां बिजली बिलों का भार कम हुआ है वहीं विद्युत विभाग को बिजली बेच कर फायदा भी उठा रहे हैं। *(रा.प., 14.10.21)*

बिजली बचाने के लिए एनर्जी ऑडिट

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश में अड़ानी, मित्तल, जेएसडब्लू सहित 16 बड़े निवेशकों ने सोलर प्लांट लगाने के लिए 2.59 लाख करोड़ रुपए का निवेश का एमओयू व एलओआई किया है। इसके साथ ही पहले से ही कई प्लांट लग रहे हैं। इससे अब प्रदेश सोलर हब बन गया है।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा की बचत भी उत्पादन है। इसके लिए युवाओं और बच्चों को ऊर्जा बचत का संदेश देना होगा। आवश्यकता नहीं होने पर विद्युत उपकरणों को बंद करे और कम ऊर्जा खपत वाले विद्युत उपकरणों का उपयोग करें। उन्होंने बताया कि पीएम किसान योजना व अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देशभर में अग्रणी है।

बिजली बचाने के लिए एनर्जी ऑडिट करवाई जा रही है और बिजली छीजत रोकने और गुणवत्तायुक्त बिजली सप्लाई की पहल की जा रही है। केंद्र के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने राजस्थान को फ्रंट रनर राज्य घोषित किया है। *(दै.भा., 15.12.21)*

कोयला व बिजली संकट

प्रदेश में कोयले की कमी के कारण उपजे बिजली संकट ने ऊर्जा महकमे से लेकर राज्य व केंद्र सरकार तक को हिलाकर रख दिया। बिजली उत्पादन के प्लांट बंद करने पड़े और बाजार से करोडों रुपए की महंगी बिजली खरीदी गई। आखिर इस महंगी बिजली का कंरट भी राज्य के 1.50 करोड़ उपभोक्ताओं को ही लगेगा।

विद्युत विनियामक आयोग में टैरिफ पीटिशन दायर होगी तब मंहगी बिजली खरीदने का खर्चा भी उसमें जोड़ा जाएगा। उसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। सवाल कौन खड़ा करे? आखिर इस कुप्रबंधन और ढिलाई के लिए जिम्मेदार कौन है।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बी.डी कल्ला हो या ऊर्जा सचिव सुबोध अग्रवाल अथवा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के आला अधिकारी सभी ने सफाई पेश करते हुए इस नुकसान से पल्ला झाड़ दिया। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार भी एक दूसरे को दोषी बताती रही है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं? *(रा.प., 16.10.21)*

अनदेखी से डूब रही है 'नैया पानी में'

जलदाय विभाग में अफसरों की अनदेखी के चलते जयपुर शहर में उत्तर और दक्षिण के पेयजल उपभोक्ताओं पर पानी के बिलों के 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बकाया चल रहा है। इसके बावजूद वसूली को लेकर इंजीनियर सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। इंजीनियरों का तर्क है कि काम ज्यादा होने से बकाया वसूली के लिए उनको समय नहीं मिलता।

गौरतलब यह है कि पानी के बकाया वसूली के लिए हर साल अभियान चलाया जाता है और केवल रस्म अदायगी कर इसे पूरा कर लिया जाता है। इस छपी खबर के बाद इंजीनियरों में खलबली मच गई और बकाया वसूली के लिए अब फील्ड में दौड़ लगाते फिर रहे हैं।

(रा.प., 23.11.21, 24.11.21)

नल से जल पहुंचाने में पिछड़े बड़े राज्य

देश में ग्रामीण आबादी को साफ पेयजल मुहैया कराने से जुड़ी केंद्र की हर घर नल लगाने की महत्वाकांक्षी योजना 'जल जीवन मिशन' करीब ढाई साल की हो गई है। इस अवधि में लक्ष्य हासिल करने में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई बड़े राज्य पिछड़ गए हैं। वहीं गोवा, तेलंगाना, पुडुचेरी व हरियाणा जैसे चार राज्यों और केंद्र शासित अंडमान निकोबार व दादरा नगर हवेली में टार्गेट पूरा हो गया है।

बिहार, पंजाब, हिमाचल, गुजरात लक्ष्य हासिल करने में अव्वल रहे हैं। यहां करीब 90 फीसदी काम पूरा हो गया है। कोरोना काल में 8 करोड़ 65 लाख घरों में नल लगाए गए हैं। लक्ष्य 2024 तक 19 करोड़ 22 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल मुहैया कराना है। *(रा.प., 13.12.21)*

पानी सैंपलों में पाया 'अशुद्ध' पेयजल

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश में नलों से सप्लाई हो रहे पेयजल के 37 हजार 283 सैंपल की जांच की है। इसमें से 11 हजार 61 सैंपलों में अशुद्ध पेयजल मिला है। यह सैंपल 54 प्रयोगशालाओं में जांच किए गए हैं। अशुद्ध सैंपल होने पर 174 मामलों में कार्रवाई की गई। ताकि नलों के जरिए घरों तक स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल मिल सके।

इसके लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर टेस्टिंग किट भी दिए गए हैं। इसके बावजूद जुटाए गए मामलों में पेयजल में रसायन एवं मिनरल जैसे ऑर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन व यूरेनियम सहित अन्य अशुद्धियां मिली है। पानी जांच में खरा नहीं उतरने पर इसकी अधिकारियों को ऑनलाइन जानकारी दी जा रही है । इसके बाद वहां पर शुद्ध पेयजल का इंतजाम किया जा रहा है। *(दै.भा., 18.10.21)*

बाड़मेर के गांवों की बदली तस्वीर

बाड़मेर जिले के गडरारोड, गिराब क्षेत्र के सरहदी गांवों में हर साल एक से डेढ़ मीटर भूजल स्तर गिर रहा है। इससे भूजल विभाग ने इस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर रखा है। फिर भी बॉर्डर के गांवों में हर साल दो सौ ट्यूबवैल खुद रहे हैं और अथाह पानी निकल रहा है। पिछले पांच साल में दो हजार से भी ज्यादा ट्यूबवैल खोदे गए है और भरपूर पानी से किसान सालाना लाखों रुपए की रबी की फसलें ले रहे हैं।

जिले के गडरारोड, खलीफे की बावड़ी, लालासर, कुबड़िया, गिराब, आसाड़ी समेत करीब एक दर्जन गांवों में पानी की धार ने पांच हजार किसानों की तकदीर बदल दी है। सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र के कारण यहां नया सिंचित क्षेत्र विकसित हो रहा है। यहां पर पांच सौ से छह सौ फीट की गहराई पर मीठा पानी निकल रहा है। इसे प्रकृति का करिश्मा और अच्छा संकेत माना जा रहा है। *(दै.भा., 23.10.21)*

भूजल सर्वे के आंकड़ों में जबरदस्त अंतर

देश में भूजल की गुणवत्ता आंकने और कुओं के जल की निगरानी की नीति बनी थी। इसके तहत देशभर में 50 हजार कुओं की निगरानी की योजना बनी और बजट भी आवंटित हुआ, लेकिन योजना खत्म होने के दो वर्ष बाद भी इसमें कोई प्रगति नहीं हुई, न ही डिजिकली भूजल स्तर और गुणवत्ता मापने की व्यवस्था हो पाई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने देश के भूजल मैनेजमेंट और रेगुलेशन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर सवाल खड़े किए है। भूजल सर्वे के केंद्र और राज्यों के आंकड़ों में जबरदस्त फर्क है। जहां केंद्र की रिपोर्ट में करीब 35 फीसदी में पानी में खतरनाक तत्व मिले हैं वहीं राज्य सरकारों की रिपोर्ट के अनुसार करीब 85 फीसदी में खतरनाक अवयव मिले हैं। सीएजी ने केंद्र सरकार को दोनो आंकड़ों के समायोजन से रिपोर्ट बनाने को कहा है ताकि सही स्थिति का पता चल सके। *(दै.भा. 24.12.21)*

ग्रामीण घरों में पहुंचेगा शुद्ध पेयजल

जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 2345 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। राजस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए 10,180.50 करोड़ रुपए का केंद्रीय कोष आवंटित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से करीब चार गुना ज्यादा है। सब्सिडी बढ़ने से राज्य के लाखों ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के काम में तेजी आएगी।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुशंसा पर राजस्थान के लिए यह राशि मंजूर की है। जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से अब तक प्रदेश में लगभग 9.97 लाख घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2024 तक शेष 80 लाख घरों में नल से पेयजल सप्लाई करने का लक्ष्य है। प्रदेश में अब तक 54 पानी टैस्ट लैब भी खोली जा चुकी है, जहां आम व्यक्ति पानी के सैंपल की जांच करवा सकता है।

(दै.भा., 08.12.21)

गांव-ढाणियों में हर घर पेयजल कनेक्शन

प्रदेश में मौजूदा वित्तीय वर्ष में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को 'हर घर नल कनेक्शन' देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक 1077 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मिशन के तहत गांव-ढाणियों में नल कनेक्शन देकर 10 नवम्बर तक प्रदेश के 43 हजार 323 गांवों में से 35 हजार 955 गांवों के एक्शन प्लान तैयार कर लिए गए हैं।

देश में सर्वाधिक विलेज एक्शन प्लान तैयार करके राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। राज्य में पिछले दो सालों में 11 लाख 74 हजार घरों में नल कनेक्शन किए गए।

(दै.भा., 15.11.21)

सशक्तिकरण की मिसाल बनी महिलाएं

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित नीमकाथाना और श्रीमाधोपुर क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं पुश्तैनी रोजगार एवं संस्कृति के साथ पिछले कई सालों से महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी हुई हैं। यहां के करीब 15 गांवों में सैंकड़ों महिलाएं गलीचे निर्माण के पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा रही हैं।

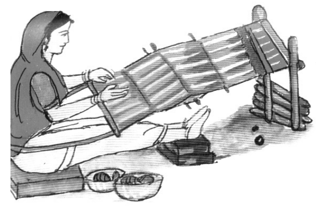

खास यह है कि यहां सास अपनी बहुओं को घर की परंपराओं के साथ लूम पर गलीचा बनाई का काम सिखाती है। जिससे यह लघु उद्योग पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। इस काम के लिए महिलाएं घरेलू कार्यों में से समय निकालती हैं। यहां तैयार होने वाले गलीचे देश ही नहीं अमरीका और यूरोप तक जाते हैं। इस परंपरा के चलते इन गांवों की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। *(रा.प., 09.11.21)*

स्वयं सहायता बना सक्षमता का मंत्र

चूल्हे-चौके में उलझी रहने वाली महिलाएं अब बिजली मीटर रीडिंग कर रही हैं, स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म सिल रही हैं, ऑक्सीजन प्लांट का संचालन कर रही हैं। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट, खिलौने, वन उत्पाद, सिलाई-कढ़ाई, मास्क निर्माण जैसे कई काम कर आर्थिक आजादी महसूस कर रही हैं। साथ ही वंचित, शोषित आदिवासी वर्ग भी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है।

यह सब हो रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए। इसके तहत स्वयं सहायता समूह बनाकर लोग सक्षम हो रहे हैं। दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। देश में 72 लाख 78 हजार से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। *(रा.प., 15.11.21)*

टेक्नोलॉजी में बाजी मार रही हैं महिलाएं

मौजूदा वक्त में महिलाएं हर क्षेत्र में न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है बल्कि पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। खासकर एजूकेशन की बात करें तो, यहां पर देश की युवा लड़कियां रोज नई इबारत लिख रही हैं। पारंपरिक पढ़ाई के अलावा स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में हमने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है।

स्टेम से ग्रेजुएशन में भारतीय बेटियां बाजी मार रही है। पहले इस क्षेत्र में पुरुषों का ही कब्जा हुआ करता था, लेकिन लड़कियों ने न केवल इस गढ़ में सेंध लगाई बल्कि अब आगे भी बढ़ गई हैं। एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक्स एंड सोसायटीज ऑफ साइंसेज इन इंडिया के मुताबिक देश में स्टेम में जितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनमें 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। *(दै.भा., 30.10.21)*

महिला व बच्चों को मिलेगी मुफ्त औषधि

निरोगी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए महिलाओं और बच्चों को एक जनवरी से निःशुल्क औषधियां मिलेंगी। स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को एनिमिया और कुपोषण जैसी बीमारियों से मुक्त करने के लिए अभियान चलाकर औषधियों का वितरण किया जाएगा।

यह जानकारी आयुर्वेद मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने देते हुए कहा कि प्रदेश के 58 ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुष चिकित्सालयों को शीघ्र क्रियाशील करने और 500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। *(दै.भा., 03.12.21)*

प्रदेश में पहली बार लिंगानुपात बढ़ा

प्रदेश में पहली बार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1009 पहुंच गई है। हालांकि अब भी बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में तस्वीर बहुत खराब है। प्रदेश 6 साल की उम्र से बड़ी 36.5 फीसदी बेटियां कभी स्कूल नहीं पहुंचती। यानी 3 में से एक लड़की ने कभी स्कूल नहीं देखा। यही नहीं गांवों में 34 फीसदी और शहरों में 17 फीसदी बेटियां आज भी 15-16 साल की उम्र में ही मां बन जाती है।

इसके खतरे शिशु और मातृ मृत्युदर ज्यादा होने और कुपोषण के साथ खून की कमी आदि के रूप में देखे जा रहे हैं। निरोगी राजस्थान के लिए यह चौंकाने वाला खुलासा 2020-21 के नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-5 में हुआ है। हालांकि, अच्छी बात है कि गांवों में लिंगानुपात काफी सुधरा है। गांवों में अब 1000 लड़कों पर 1022 लड़कियां और शहरों में प्रति 1000 पुरुषों पर 968 महिलाएं हैं। *(दै.भा., 29.11.21)*

मुख्यमंत्री ने किया योजनाओं का शुभारंभ

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में प्रदेश में महिलाओं के लिए जागृति बैक टू वर्क, आईएम शक्ति उड़ान, अनुप्रति कोचिंग और डीबीटी वाउचर योजनाओं का शुभारंभ किया है। उन्होंने जन कल्याण पोर्टल मोबाइल एप एवं ई-मित्र एट होम का शुभारंभ किया। साथ ही उड़ान योजना के शुभंकर संचार रणनीति पुस्तिका का विमोचन करते हुए प्रतिकात्मक रूप से 8 एम्बुलेंस और दो बाइक एम्बुलेंस को रवाना किया।

गहलोत ने कहा कि प्रदेश में करीब 100 एम्बुलेंस विभिन्न जिलों में भेजी जाएगी। निःशुल्क सैनेटरी नेपकीन वितरण के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने आह्वान किया है कि सभी जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ और सभी लोग मिलकर अधिक से अधिक भागीदारी के साथ इस योजना को सफल बनाया जाए, ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। *(दै.भा., 20.12.21)*

बच्चों का सरकारी स्कूलों में बढ़ा रुझान

कोरोना संक्रमण के बाद सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में बड़ा बदलाव आया है। बच्चों का निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों की ओर पलायन हुआ है। इससे निजी स्कूलों में नामांकन घटा है और सरकारी स्कूलों में नामांकन तेजी से बढ़ा है। 16वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2021 से यह स्थिति सामने आई है।

कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की घर पर पढ़ाई और स्कूल खुलने पर परिवारों और विद्यालयों के सामने आई चुनौतियों पर तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 6-14 आयु वर्ग के बच्चों का निजी स्कूलों में नामांकन 2018 में 32.5 प्रतिशत से घटकर 2021 में 24.4 प्रतिशत हो गया। वहीं 15-16 आयु वर्ग के बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन 57.4 प्रतिशत से बढ़कर 67.4 फीसदी हो गया। *(रा.प., 18.11.21)*

'कट्स' ने दायर की बसों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर एनजीटी में याचिका

'कट्स' द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल) में हॉकिंग पर नियंत्रण और निजी व रोडवेज बसों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की है। याचिका में राजस्थान सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। एनजीटी ने याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के गृह, परिवहन विभाग प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं मुख्य सचिव के नाम नोटिस जारी किए हैं। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का कहा है।

उक्त याचिका पर्यावरण संरक्षण के तहत ध्वनि प्रदूषण, खासतौर पर वाहनों द्वारा 'हॉकिंग' से उत्पन्न शोर को लक्ष्य बनाते हुए दायर की गई है। गौरतलब है कि 'कट्स' पिछले कुछ अरसे से ध्वनि प्रदूषण और हॉकिंग पर नियंत्रण के लिए अभियान चला रहा है और सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व के माध्यम से पैरवी भी की है।

याचिका में न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया गया है कि 'हॉकिंग' मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन इनकी कड़ाई से पालना नहीं होने से देश की सड़कों पर अभिशाप बन गया है। अनाधिकृत रूप से वाहनों में 'प्रेशर हॉर्न' का उपयोग इस समस्या को और भी ज्यादा गंभीर बना रहे हैं।

याचिका में एनजीटी से यह भी मांग की गई है कि पूर्व में दिल्ली सरकार को दिए गए फैसले के अनुरूप 'हॉकर्स' पर पर्यावरण मुआवजा राजस्थान में भी लागू किया जाए और पर्यावरण हितार्थ 'पर्यावरण कोष' के नाम अलग से कोष बनाया जाकर वसूली गई मुआवजा राशि उसमें जमा की जाए।

देश में जयपुर ट्रैफिक दुर्घटनाओं में आगे

ट्रैफिक दुर्घटनाओं और उनमें हुई मौतों के मामले में जयपुर ने मुंबई, पुणे, सूरत जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 2020 में लॉकडाउन के बावजूद जयपुर में काफी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हुईं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार जयपुर पिछले साल ट्रैफिक दुर्घटनाओं के मामले में देश के बड़े 53 शहरों में छठे और दुर्घटना से हुई मौतों के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है।

जयपुर में पिछले एक साल में 2041 ट्रैफिक दुर्घटनाएं हुई। इनमें से 1940 सड़क दुर्घटना और 101 रेलवे दुर्घटनाएं थीं। जयपुर से अधिक दुर्घटनाएं बेंगलुरू में 3233, चेन्नई में 4389, दिल्ली (शहर) में 4556, हैदराबाद में 2065, इंदौर में 2112 हुई। वहीं हादसों से हुई मौत के मामले में बेंगलुरू, हैदराबाद और इंदौर जयपुर से पीछे है। दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौत दिल्ली में हुई। यहां 1568 लोग मरे। दूसरे नंबर पर चेन्नई में 872 मौतें और तीसरे नंबर पर जयपुर में 708 मौतें हुईं। जयपुर में 606 लोग सड़क दुर्घटनाओं में तथा 102 लोग रेल दुर्घटना के शिकार हुए। 2020 में पूरे देश में 48,967 ट्रैफिक दुर्घटनाएं हुईं। *(रा.प., 04.11.21)*

सड़क हादसे ज्यादा क्यों: होगी समीक्षा

तमिलनाडु की तर्ज पर अब राजस्थान में भी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस (आईआरएडी) के जरिए सड़क हादसों की समीक्षा हो सकेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 राज्यों में इसकी शुरुआत की है। राजस्थान में प्रथम चरण में जयपुर, जोधपुर, अलवर और अजमेर में यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। जिससे सड़क हादसों के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सकेगा।

इस सिस्टम को वाहन और सारथी नामक सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के नंबर डालते ही पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। ड्राइवर के लाइसेंस के बारे में भी पता चल सकेगा। आईआरएडी में एक जनवरी 2021 से अब तक लगभग 30178 सड़क हादसों की एंट्री हो चुकी है। इसमें 6500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस एप होगा, जिसका पासवर्ड संबंधित पुलिस और आरटीओ अधिकारियों को दिया गया है। वे सड़क हादसा होने पर मौके पर जाएंगे और मौका मुआना कर पूरे विवरण सहित हादसों के कारणों का एप में उल्लेख करेंगे।

पीडब्लूडी अफसर भी रोड इंजीनियरिंग की खामियों और ब्लैक स्पॉटस के बारे में एप में उल्लेख करेंगे। चिकित्सा विभाग बताएगा कि घायल व्यक्तियों को कितने समय में इलाज मिला, दुर्घटना स्थल से चिकित्सा सुविधा कितनी दूर है। ऐसी रिपोर्टस की समीक्षा के बाद संबंधित विभाग सुधार करेंगे। *(दै.भा., 04.11.21)*

प्रदेश में सड़क हादसों में 36,585 मौतें

प्रदेश में पिछले कुछ सालों से सड़क हादसों में मौतों के आंकड़ों पर नजर डाले तो सामने आया कि साढ़े तीन साल में 36 हजार 585 मौतें हुई और उनमें सबसे ज्यादा युवा थे। इन हादसों में 19 हजार से ज्यादा युवाओं की मौत हुई, जिनकी उम्र 18-35 साल थी। इस साल अगस्त तक प्रदेश में करीब 13 हजार 581 सड़क दुर्घटनाएं हुई। उनमें 6 हजार 452 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 12 हजार 482 घायल इन दुर्घटनाओं का दर्द झेल चुके हैं। पुलिस और ट्रांसपोर्ट के एनालिसिस में सामने आया है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का कारण ओवर स्पीड है। इसके बाद लापरवाही व शराब पीकर वाहन चलाने से एक्सीडेंट होते हैं।

राजस्थान में अगस्त तक 2020 के मुकाबले सड़क दुर्घटनाओं में करीब 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। पूरे प्रदेश में इस साल अगस्त तक 13 हजार 581 एक्सीडेंट हुए, जो पिछले साल 11 हजार 696 हुए थे। प्रदेश में 2021 में अगस्त तक सबसे ज्यादा सड़क हादसों की बात करें ता वह उदयपुर जिले में हुए। उदयपुर में 789 एक्सीडेंट हुए जिनमें 357 लोगों की जान गई । अजमेर में 699 एक्सीडेंट में 321, जयपुर पूर्व में 439, पश्चिम में 455, उत्तर में 120, दक्षिण में 352 और ग्रामीण में 670 एक्सीडेंट हुए। इन पांचों इलाकों में मिला कर 673 लोगों की मौत हुई। *(दै.भा., 11.11.21)*

उपभोक्ता फैसले

एसबीआई बैंक को भारी पड़ा खाते से राशि निकलने का मैसेज नहीं भेजना

मालवीय नगर निवासी श्रीराम मीणा ने जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-4 में एसबीआई बैंक के खिलाफ परिवाद दायर किया। उन्होंने दर्ज परिवाद में आयोग को बताया कि उनका एसबीआई बैंक में खाता है। उनके खाते से 09 अप्रेल से 13 अप्रेल 2017 के बीच साइबर ठगों ने एक लाख 28 हजार रुपए निकाल लिए। मोबाइल पर 13 अप्रेल को राशि निकासी का मैसेज मिलने पर उन्होंने बैंक जाकर ऑनलाइन खरीदारी को रुकवाया। इससे उनके खाते में 42,525 रुपए तो वापस जमा हो गए, लेकिन उन्हें 86 हजार 275 रुपए का नुकसान हो गया। यदि उन्हें बैंक द्वारा समय पर मैसेज दिया होता तो उन्हें यह नुकसान नहीं होता।

मामले की सुनवाई पर दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद आयोग ने माना कि मैसेज भेजने के लिए बैंक 15 रुपए शुल्क वसूलता है। अगर समय पर मैसेज मिलता तो ठगी से बचा जा सकता था। आयोग ने इसे सेवादोष करार दिया और एसबीआई बैंक को आदेश दिया है कि साइबर ठगों द्वारा निकाली गई 86 हजार 275 रुपए की राशि 9 फीसदी ब्याज सहित परिवादी श्रीराम मीणा को वापस की जाए। साथ ही आयोग ने 15 हजार रुपए बतौर मानसिक संताप और 10 हजार रुपए परिवाद व्यय के भी अलग से अदा करने का निर्देश दिए हैं। *(रा.प. एवं दै.भा., 09.11.21)*

फैक्ट्री में आग से हुआ नुकसानः बीमा कंपनी को देनी होगी क्षतिपूर्ति

राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर में मैसर्स रिषभ इंपैक्स ने बीमा कंपनी दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि उसकी अजमेर में मधुबन औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में 11 नवंबर 2016 में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। आग लगने से करीब 85 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कंपनी की ओर से बीमा कंपनी में आग लगने से हुई इस क्षति के मुआवजे के लिए दावा पेश किया गया। लेकिन बीमा कंपनी ने मात्र 16.86 लाख रुपए का क्लेम मंजूर किया। कंपनी मालिकों द्वारा वापस 58.26 लाख रुपए का संशोधित दावा पेश किया गया।

राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य सुरेंद्र कुमार जैन व सदस्य शैलेंद्र भट्ट ने मामले की सुनवाई कर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी को 27.40 लाख रुपए क्षतिपूर्ति स्वरूप अदा करे। साथ ही इस राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख से 9 फीसदी ब्याज और परिवाद खर्च 25 हजार रुपए भी परिवादी को अलग से दिए जाएं। *(दै.भा., 11.12.21)*

ग्रीन एक्शन वीक अभियान

शेयरिंग की भावना के लिए जागरूकता लाना आवश्यक

''हमारे समाज में शेयरिंग की भावना को पुनः स्थापित करने के लिए समाज में जागरूकता लाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाना होगा।''

उक्त संदेश 'कट्स' द्वारा ग्रीन एक्शन वीक, राजस्थान के अन्तर्गत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में जिला प्रमुख रमा चोपड़ा ने दिया। कार्यक्रम में जयपुर नगर निगम, हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर ने अपने उद्बोधन के दौरान बताया कि जिस कचरे को हम कचरा समझते हैं और मुन्सिपल कॉरपोरेशन के लिए सिरदर्द बना हुआ है, उसी से 'कबाड़ से जुगाड़' के माध्यम से 'कट्स' और इसकी सहयोगी संस्थाओं ने इतने अच्छे उत्पाद बनाए हैं, जो कि प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि हमें हमारे शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इसकी शुरुआत प्रत्येक घर से करनी होगी।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने बताया कि 'ग्रीन एक्शन वीक' प्रति वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। यह अंतरर्राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जो सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन, स्वीड़न के सहयोग से वैश्विक स्तर पर आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर 'कट्स' के निदेशक, जॉर्ज चेरियन ने कहा कि सतत् उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 'कट्स' द्वारा इस अभियान को राजस्थान के अलावा भारत के 12 अलग अलग राज्यों में संचालित किया जा रहा है। उन्होंने वस्तुओं के रीयूज, रिसाईकल का हवाला देते हुए रेखीय अर्थव्यवस्था को त्याग कर चक्रिय अर्थव्यवस्था को अपनाने का आह्वान किया।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मुख्य अभियंता डॉ. वी.के.सिंघल ने कचरा प्रबंधन और ई-वेस्ट के बारे में कई जानकारियों को साझा करते हुए कहा कि आम आदमी में व्यवहारिक परिवर्तन और जागरूकता लाना जरूरी है। कार्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. सोमन्ना दत्ता ने 'शेयरिंग कम्यूनिटी' (साझेदार समाज) के बहुत सारे उदाहरण दिए और उनके अनुसार काम करने करने की जरूरत पर बल दिया।

'ग्रीन एक्शन वीक' अभियान की कार्यक्रम अधिकारी निमिषा शर्मा ने कार्यशाला के प्रारंभ में अभियान के तहत की गई विभिन्न गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया। इस अवसर पर महिला समुदाय द्वारा बनाए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

स्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)